हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
(तिथि 2 अगस्त 2024, समय 1305 (5 मिनट))

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की अध्यक्षता में दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में शुरु हो गया है। यह राष्ट्रपति के सञ्चालन में राज्यपालों का पहला सम्मेलन है और सभी राज्यों के राज्यपाल इस बैठक में भाग ले रहे हैं। उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और गृह मन्त्री अमित शाह तथा केन्द्रीय मन्त्री शिवराज सिह्न चौहान, धर्मेन्द्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और डॉक्टर मनसुख माण्डविया भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय और गृह मन्त्रालय में मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। बैठक की कार्यसूची में तीन आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा जनजातीय क्षेत्रों, आकाक्षी जिलों और विभिन्न खण्डों या सीमावर्ती इलाकों जैसे ध्यान देने वाले क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा **माई भारत**, **एक भारत श्रेष्ठ भारत** और **एक वृक्ष मां के नाम** तथा **प्राकृतिक खेती** जैसे कई अभियानों में राज्यपालों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यपालों की भूमिका और राज्यों में विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श होगा। राज्यपाल विभिन्न अलग-अलग समूहों में इन विषयों पर बातचीत करेंगे। समापन सत्र में ये समूह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और अन्य प्रतिभागियों के समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा वर्ग के अधिकार सुरक्षित किए हैं। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों, एमबीबीएस सहित केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों में दाखिले में आरक्षण का प्रावधान भी पिछड़ा वर्ग के लिए किया है। इतना ही नहीं, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की है। इसी प्रकार, हरियाणा में भी हमारी डबल इंजन की सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके अधिकार दे रही है। मुख्यमंत्री कल हरियाणा पिछड़ा आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश (सेवानिवृत) दर्शन सिंह द्वारा हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-बी के लिए आरक्षण के अनुपात पर अनुपूरक रिपोर्ट देने उपरांत उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए उद्यम स्थापित करने के लिए पहली बार वेंचर कैपिटल फंड बनाने की भी शुरुआत की है। हरियाणा में भी राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग-ए के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग-बी के लिए यह अतिरिक्त प्रावधान होगा।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि आज दुनिया में भारत का नाम हरियाणा के खिलाड़ियों ने रोशन किया है। वर्तमान राज्य सरकार की खेल नीति के परिणामस्वरूप पेरिस ओलम्पिक में हरियाणा के दो खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर दुनिया में परचम लहराने का काम किया है जिसके लिए उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को बधाई व शुभाकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल चण्डीगढ़ से दिल्ली के ट्रेन के सफर के पश्चात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे जाबांज खिलाड़ियों ने उत्कृष्ठ प्रदर्शन करके हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम तीसरी बार सरकार बनाकर हरियाणा में विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगें।

****

हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान-2023 के कार्यान्वयन में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। जल शक्ति अभियानः कैच द रेन-2024' के तहत राज्य में ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देने के लिए 65,000 से अधिक वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 18,104 जलाशयों की जियोटैगिंग की गई है। इनमें से 852 जलाशयों का नवीनीकरण किया गया और 1,152 जलाशयों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 40,000 से अधिक पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं, 10,000 वाटरशेड विकास संरचनाओं का निर्माण और 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि किसानों और आमजन को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए लगभग 70,000 प्रशिक्षण कार्यक्रम और किसान मेले आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए और सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जिला-विशिष्ट जल संरक्षण योजनाएं भी विकसित की गई हैं। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से चिन्हित 10 जिले जींद, फतेहाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, महेन्द्रगढ़, रेवाडी, कैथल, गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्प्रिंग शेड एरिया में वैज्ञानिक वनीकरण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सरकारी भवनों और वन भूमि पर वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना और जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो, जल स्रोतों में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की जल शक्ति अभियानः कैच द रेन-2024 के प्रभावी निष्पादन के लिए नोडल आफिसर नियुक्त किये जायेंगे ।